सिकंदराबाद हैदराबाद होटल मालिक और

बनाम

हैदराबाद नगरपालिका निगम, हैदराबाद और अन्य

20 जनवरी, 1999

[श्रीमती सुजाता बनाम मनोहर और ए.पी. मिश्रा, जे.जे.]

नगरपालिकाएँः

हैदराबाद नगर निगम अधिनियम, 1955: धारा 169, 174, 197, 198, 230, 521(1)(ई) और 622

लाइसेंस शुल्क-व्यापार लाइसेंस-आवास, होटल, रेज़ चलाने के लिए टॉरेंट, कॉफी हाउस, चाय की दुकान, खाने का घर, शीतल पेय की दुकान, कैफेटेरिया, टिफिन रूम आदि - एस.एस. के तहत जारी किए गए 6.4.1981 और 25.7.1992 दिनांकित आदेशों द्वारा वृद्धि। 521 (1) (ई) और 622-कर या शुल्क-नगर निगम को यह सुनिश्चित करने के लिए परिसर का निरीक्षण करना आवश्यक है कि लाइसेंस की शर्तों का पालन किया गया था। खाद्य पदार्थों की बिक्री के साथ और पर्यवेक्षण और इन परिसरों में स्वच्छता, कचरा हटाने और स्वच्छता के रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए-लाइसेंस शुल्क था। निगम की सामान्य निधि में जमा किया जाता है लेकिन शुल्क को उन उद्देश्यों के लिए निर्धारित किया जाता है जिनके लिए

वे बजट अनुमान नियमों की धारा 6 के तहत एकत्र किए गए थे, ऐसी परिस्थितियों में, शुल्क एक शुल्क है, न कि कर-उद्देश्य नियामक और क्षतिपूर्ति उद्देश्यों के लिए शुल्क लगाना है-यह तर्क कि शुल्क की आड़ में शुल्क एक कर है, खारिज कर दिया जाता है, आगे यह तर्क दिया जाता है कि एस.एस. के साथ गैर-अनुपालन। 197 और 198 ने लेवी को अमान्य कर दिया, अस्वीकार कर दिया गया-धारा 230 के तहत संरक्षण कर लागू करने की निगम की शक्ति उक्त शुल्क की प्रकृति को प्रभावित नहीं करती है। इसे लागू करने के लिए कोई पारस्परिक लाभ आवश्यक नहीं है। ऐसा शुल्क यदि ऐसी गतिविधि को विनियमित करने के लिए शुल्क लिया जाता है लेकिन यह अत्यधिक नहीं हो सकता है-तथ्यों पर, शुल्क अत्यधिक नहीं है।

शुल्क या कर-का निर्धारण-विनियामक शुल्क दिए गए लाइसेंस की प्रकृति पर निर्भर करता है-एक अलग निधि का निर्माण-आवश्यक नहीं-इसके उद्देश्यों के लिए राशि को चिह्नित करना हैदराबाद नगर निगम अनुमान नियम, 1968, आर. 6 के लिए पर्याप्त है।

आवास या भोजनालय आदि चलाने के लिए लाइसेंस शुल्क-संबंधित परिसर के किराए के आधार पर निर्धारित करने की दर-आयोजित की वैधता, किराए का नगर निगम द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा से कोई संबंध नहीं है। राज्य-इसलिए किराए के आधार पर परिसरों के वर्गीकरण

का संबंध शुल्क की मात्रा से है-साथ ही नौ साल के बाद शुल्क को दोगुना करना, सिवाय इसके भारत का संविधान 1950, अनुच्छेद 14

प्रत्यर्थी-निगम ने एक व्यापार के लिए लाइसेंस शुल्क बढ़ा दिया धारा के तहत आवास, होटल, रेस्तरां, कॉफी हाउस, चाय की दुकान, खाने का घर, शीतल पेय की दुकान, टिफिन रूम आदि चलाने के लिए लाइसेंस लगाया जाता है। 622 हैदराबाद नगर निगम अधिनियम, 1955 की धारा 521 (1) (ई) और 622 के तहत जारी किए गए आदेशों द्वारा। याचिकाकर्ताओं ने इस अदालत के समक्ष वर्तमान रिट याचिका दायर की थी लाइसेंस शुल्क में उपरोक्त वृद्धि को चुनौती देना।

याचिकाकर्ताओं की ओर से यह तर्क दिया गया कि कोई प्रतिदान नहीं था प्रत्यर्थी द्वारा प्रभारित लाइसेंस शुल्क और विचाराधीन व्यापारियों को प्रदान की गई सेवाओं के बीच यथास्थिति, कि एकत्र की गई राशि लाइसेंस शुल्क नगर निगम के सामान्य कोष में जमा किया गया था धारा 174 और इसलिए में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना धारा 197 और 198 लाइसेंस शुल्क में वृद्धि अमान्य थी, यहां तक कि संबंधित परिसर के संबंध में देय किराए के आधार पर लाइसेंस शुल्क अनुचित था क्योंकि किराए का प्रदान की गई सेवाओं के साथ कोई संबंध नहीं था निगम।

याचिका खारिज करते हुए, यह अदालत

अभीनिर्धारित: 1.1. सवाल, जिस पर विचार करने की आवश्यकता है, यह है कि क्या 1981 और 1992 के आदेशों के तहत बढ़ा हुआ लाइसेंस शुल्क प्रकृति में है। कर या शुल्क। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए यह देखना आवश्यक है कि अनुज्ञप्ति की प्रकृति जो प्रदान की जाती है। होटल लाइसेंस जो जारी किया गया है प्रत्येक व्यापारी के लिए उप-कानूनों में निर्धारित शर्तों के अधीन है। खाने के घरों के विनियमन से संबंधित नगर निगम का या हैदराबाद नगर निगम की धारा 521 में उल्लिखित होटल यह सुनिश्चित करने के लिए कि शर्तों का पालन किया जा रहा है, विचाराधीन परिसर के साथ। बिक्री के निरीक्षण और पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी भी इसकी है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि लाइसेंस की सभी शर्तें इस तरह के भोजन की तैयारी और बिक्री का अनुपालन किया जाता है।

1.2. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि लाइसेंस शुल्क या तो नियामक या प्रतिपूरक हो सकता है। जब विशिष्ट सेवाएँ प्रदान करने के लिए शुल्क लिया जाता है। प्रदान की गई सेवाओं और लिए गए शुल्क के बीच क्विड प्रो क्वो का कुछ तत्व होना चाहिए ताकि लाइसेंस शुल्क सेवा प्रदान करने की लागत के अनुरूप हो, हालांकि सटीक अंकगणितीय समानता की उम्मीद नहीं है। हालाँकि, यह एकमात्र प्रकार का शुल्क नहीं है, जिससे शुल्क लिया जा सकता है। लाइसेंस शुल्क तब भी विनियामक

हो सकता है जब उन गतिविधियों को विनियमित या नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है जिनके लिए लाइसेंस दिया जाता है।

आयुक्त, एच.आर.ई., मद्रास बनाम श्री लक्ष्मींद्र तीर्थ स्वामी, श्री शिरपुर मठ, [1954] एससीआर 1005, कलकत्ता निगम बनाम स्वतंत्रता सिनेमा, [1965] 2 एससीआर 477, इंडियन माइका एंड माइकेनाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम बिहार राज्य, [1971] पूरक, एस.सी.आर. 319, ओमप्रकाश अग्रवाल बनाम गिरिराज किशोरी, [1986] 1 एस.सी.आर. 149, नगर परिषद मदुरै बनाम आर. नारायणन, [1976] 1 एससीआर 333 और कृषि उपज मंडी समिति बनाम ओरिएंट पेपर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, [1995] 1 एस.सी.सी. 655, पर निर्भर था।

मैथ्यूज बनाम चिकोरी विपणन बोर्ड, 60 सी.एल.आर. 263, 276 का उल्लेख किया गया है।

2.1. हालाँकि, वर्तमान मामले में प्रभारित शुल्क केवल प्रदान की गई सेवाओं के लिए नहीं हैं, बल्कि उनमें एक नियामक शुल्क का एक बड़ा तत्व भी है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे लाइसेंस के नियमों और शर्तों का पालन करते हैं, लाइसेंसधारक की गतिविधि की निगरानी के उद्देश्य से लगाया जाता है। [154- डी]

वाम ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, [1997] 2 एस.सी.सी. 715, पी. कन्नदासन बनाम टी.एन. राज्य, [1996] 5

एस.सी.सी. 670 और त्रिपुरा राज्य बनाम सुधीर रंजन नाथ, [1997] 3 एस.सी.सी. 665 पर भरोसा किया।

2.2. विनियामक शुल्क के मामले में एक अलग निधि आवश्यक नहीं है। शुल्क, हालांकि सामान्य निधि में जमा किया जाता है, [1999] 1 एस.सी.आर. के लिए निर्धारित किया जाता है। जिन उद्देश्यों के लिए उन्हें एकत्र किया जाता है। स्पष्ट रूप से, इसलिए, इरादा है एक शुल्क लगाने के लिए, जिसका उपयोग वर्तमान मामले में नियामक और प्रतिपूरक उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि यह शुल्क की आड़ में एक कर टिकाऊ नहीं है। [155-एफ, 156-सी]

सिरसिल्क लिमिटेड बनाम कपड़ा समिति, [1986] सप.880, पर भरोसा किया।

2.3. यह आवश्यक नहीं है कि शुल्क केवल एकमुश्त शुल्क के रूप में होना चाहिए। वर्तमान मामले की तरह शुल्क को भी वर्गीकृत किया जा सकता है। निगम प्रभारित किए जाने वाले शुल्क की मात्रा के लिए मानदंड के रूप में भुगतान किए गए किराए की मात्रा को चुना है। उस संबंध में कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत किराए का उस क्षेत्र के साथ संबंध है जिस पर रहने का घर या खाने का घर है। स्वच्छता और स्वच्छता की आवश्यकता, कचरा उत्पादन और विनियमन की सीमा जो आवश्यक हो सकती है, परिसर के आकार पर निर्भर करती है जो बदले में गतिविधि की

सीमा को नियंत्रित करती है। निस्संदेह किसी मामले में यदि परिसर पुराना है, तो किराया कम हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भुगतान किए गए किराए के आधार पर परिसर को वर्गीकृत करने का शुल्क की मात्रा से कोई संबंध नहीं है। [156- ई-जी]

3.1. इस तथ्य को देखते हुए कि एकत्र किया गया लाइसेंस शुल्क नगर निगम द्वारा किए गए कुल खर्च का केवल एक बहुत छोटा हिस्सा है। इसलिए, इन शुल्कों के स्तर को अत्यधिक रखना संभव नहीं है। उच्च न्यायालय ने उचित रूप से विचार किया है कि नगर निगम द्वारा की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों की लागत में वृद्धि को देखते हुए दोगुना हो गया है नौ साल के बाद लाइसेंस शुल्क को अत्यधिक वृद्धि नहीं माना जा सकता है। 1987 के लाइसेंस शुल्क के स्तर से 1992 के लाइसेंस शुल्क के स्तर तक की वृद्धि के संबंध में प्रारंभिक वृद्धि को अत्यधिक माना जा सकता था। लेकिन लाइसेंस शुल्क में वृद्धि से प्रभावित विभिन्न व्यापारियों द्वारा प्रत्यर्थी-निगम को अभ्यावेदन दिए जाने के बाद नगर निगम ने वृद्धि को कम कर दिया और इसे 1987 में लिए गए लाइसेंस शुल्क से दोगुना कर दिया। लाइसेंस शुल्क में वृद्धि से व्यथित व्यापारियों ने एक जुड़वां शहरों के व्यापारियों की संयुक्त कार्रवाई समिति का गठन किया और विभिन्न स्तरों पर प्रतिनिधि भेजे। 22.4.1992, 4.5.1992, 6.5.1992, 11.5.1992 और 12.5.1992 पर संयुक्त बैठकें आयोजित की गईं और

विचारों के बड़े बदलाव के बाद सर्वसम्मति से व्यापार लाइसेंस बढ़ाने का संकल्प लिया गया। अक्टूबर 1991 में वृद्धि से पहले प्रचलित दरों पर 100% द्वारा शुल्क। इसके लिए समझौता हो गया है। निगम की स्थायी समिति और आम निकाय ने इन प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया। तदनुसार, संशोधित दरों को लागू किया गया। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि उनके सदस्य इस वृद्धि के लिए सहमत नहीं थे। फिर भी व्यापारियों, संयुक्त कार्रवाई समिति, जिसमें समान व्यापार करने वाले कई अन्य व्यापारी शामिल थे, इस वृद्धि को उचित मानते हुए सहमत हुई। इसलिए इस सहमत वृद्धि को अत्यधिक या अत्यधिक कहना उचित नहीं होगा। यह दर्शाता है कि यह शुल्क के बजाय कर लगाने का उपाय था। [158- ए-एच]

नागरिक मूल न्यायनिर्णयः 1992 की रिट याचिका संख्या 238 आदि।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत।

याचिकाकर्ताओं के लिए जी.एल. सांघी, एस.के. मेहता और सुश्री शोभा।

सी.ए. संख्या 546/91 में अपीलार्थी के लिए ए. सुब्बा राव।

सुश्री के. अमरेश्वरी, ए.के. तांडले और जी. प्रभाकर (एन.पी.) प्रत्यर्थी संख्या 2 के लिए।

पी.पी. राव, निखिल नय्यर T.V.S.N चारी प्रत्यर्थी संख्या 1 के लिए।

उत्तरदाता की ओर से के. राम कुमार, सुश्री आशा, जी. नायर, सुश्री शांति नारायणन।

न्यायालय का निर्णय

श्रीमती सुजाता बनाम मनोहर जे. इन कार्यवाहियों में याचिकाकर्ता व्यापार लाइसेंस के लिए लाइसेंस शुल्क में वृद्धि को चुनौती दे रहे हैं। हैदराबाद नगर निगम अधिनियम, 1955 की धारा 622 के तहत लगाए गए आवास, होटल रेस्तरां, कॉफी हाउस, चाय की दुकान, खाने का घर, शीतल पेय की दुकान, कैफेटेरिया, टिफिन रूम आदि चलाने के लिए।

1955 के हैदराबाद नगर निगम अधिनियम की धारा 521(1)(ई)(ii) के तहत, आयुक्त द्वारा दिए गए लाइसेंस के नियमों और शर्तों के तहत और उनके अनुरूप को छोड़कर कोई भी व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं करेगा। अन्य रूप से किसी भी परिसर में या उस पर किसी भी व्यापार या संचालन को जारी रखने की अनुमति दें, जो आयुक्त की राय में, जीवन, स्वास्थ्य या संपत्ति के लिए खतरनाक है या इसके कारण उपद्रव पैदा करने की संभावना है। प्रकृति या जिस तरीके से या उन स्थितियों के कारण जिनके तहत वही है या इसे जारी रखने का प्रस्ताव है। विशेष अधिकारी हैदराबाद नगर निगम के एक आदेश द्वारा दिनांक 15.4.1972 [1999] 1 एस.सी.आर. धारा 521(1)(ई)(ii) द्वारा कवर किए गए व्यापार, संचालन आदि को अधिसूचित

किया गया था। इस तरह से कवर किए गए व्यवसायों में खाने के घर, होटल, रेस्तरां, कैफे, बार, चाय की दुकानें, कैंटीन, कॉफी हाउस, टिफिन रूम, कैफेटेरिया या कोई भी स्थान जहाँ भोजन तैयार किया जाता है और लाभ के उद्देश्य से आपूर्ति या बेचा जाता है। ठहराव घरों को भी ढक दिया गया था।

हैदराबाद नगर निगम अधिनियम, 1955 की धारा 622 के तहत जब भी अधिनियम की तहत यह प्रावधान किय जाता है कि किसी भी उद्वेष्य के लिए लाईसेंस या लिखित अनुमति दी जा सकती है, तो ऐसे लाईसेंस या लिखित अनुमति में वह अवधि निर्दिष्ट होगी जिसके लिए औरा प्रतिबंध और शर्तें जिसके अधीन, वही प्रदान किया जाता है। धारा 622(2) के तहत ऐसे प्रत्येक लाईसेंस या लिखित अनुमति के लिए ऐसी दर पर शुल्क लिया जा सकता है जो समय-समय पर निगम की मंजूरी के साथ आयुक्त द्वारा तय किया जाएगा। 15.04.1972 के उक्त आदेश के तहत उक्त ट्रेडो के लिए लाईसेंस शुल्क निर्दिष्ट/संशोधित किया गया था। जहां भोजनालय आदि का मासिक किराया रूपये लाईसेंस फीस की दर 50/-रूपये, लाईसेंस फीस को परिसर के किराए के आधार पर वर्गीकृत किया गया था। अधिकतम लाईसेंस शुल्क जहां किराया 1000/-रूपये से अधिक था। आवास गृहों के संबंध में भी यही स्थिति थी जहां लाईसेंस शुल्क की दरें 50/- से 1000/- रूपये तक परिसर के मासिक किराए के आधार पर थी। इस प्रकार

निर्धारित दरें पहले लागू दरों से अधिक थी। इस वृद्धि को चुनौती दी गई, लेकिन उच्च न्यायालय ने इसे बरकरार रखा।

इसके बाद विशेष अधिकारी, नगर निगम हैदराबाद, उनके आदेश डी.टी.डी. 6.4.1981 इन लाइसेंस शुल्कों को संशोधित किया गया। अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया है कि सेवा शुल्क में वृद्धि को देखते हुए हैदराबाद नगर निगम द्वारा प्रस्तुत, यह आवश्यक महसूस किया गया था धारा के तहत निर्धारित लाइसेंस शुल्क की दरों की मौजूदा अनुसूची को संशोधित करना। 622(2) हैदराबाद नगर निगम अधिनियम, 1955, इसके परिणामस्वरूप यह संशोधन लाइसेंस शुल्क जहां मासिक किराया रुपये 50/- रूपये तक था, 100/-रूपये तक बढ़ाया गया। जहां मासिक किराया 1500/- से उपर लेकिन 2000/- से कम था, वहां अधिकतम लाईसेंस शुल्क 2000/- बढ़ाया गया। इसी प्रकार जहां मासिक किराया 4000/- से उपर लेकिन 5000/- से कम था, वहां अधिकतम लाईसेंस शुल्क 5000/- तक बढ़ाया गया। उक्त आदेश द्वारा सभी श्रेणियों के आवास गृहों एवं भोजनालयों के संबंध में लाईसेंस शुल्क में आनुपातिक वृद्धि की गई थी।

वर्तमान याचिकाकर्ताओं ने 1981 में रिट याचिका संख्या 3055 दायर की आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने लाइसेंस शुल्क में वृद्धि को चुनौती देते हुए 6.4.1981 के उक्त क्रम से। लर्नड सिंगल जज ने लेवी को बरकरार रखा और रिट याचिका को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर उच्च

न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष एक अपील को भी खंड पीठ ने खारिज कर दिया। डिवीजन बेंच ने कहा कि चूंकि निगम प्रदान कर रहा है याचिकाकर्ताओं के परिसरों के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के रूप में सेवाएं, और पूरे शहर में कचरा उठाने जैसी सामान्य सेवाएं भी प्रदान कर रहा है, जिसके लिए कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, निगम प्रदान कर रहा है व्यक्तियों या व्यापारियों के लिए सेवाएं, हालांकि सामान्य प्रकृति की हैं। शुल्क कोई कर नहीं है। इसने शुल्क के रूप में शुल्क को बरकरार रखा। सिविल अपील सं। 1811 और 1988 का 1812 उच्च न्यायालय की खंड पीठ के उक्त निर्णय के विरुद्ध है।

1987 में प्रतिवादी-निगम को फिर से संशोधित और बढ़ाया गया। लाइसेंस शुल्क। उक्त वृद्धि उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती के अधीन है। इसके बाद 12.10.1991 दिनांकित एक आदेश द्वारा प्रतिवादी-निगम ने फिर से खाने के घरों और रहने के घरों के लाइसेंस शुल्क में वृद्धि की। द इन क्रीज 1987 में निर्धारित लाइसेंस शुल्क का चार गुना था। हालाँकि, 25.7.1992 पर उत्तरदाताओं ने निगम और प्रभावित व्यापारियों के कई समूहों के बीच हुए समझौते के आधार पर इस वृद्धि को कम किया है। 25.7.1992 के आदेश के तहत बढ़ा हुआ लाइसेंस शुल्क 1987 के आदेश के तहत लिए गए लाइसेंस शुल्क से दोगुना है। याचिकाकर्ता समझौते के पक्षकार नहीं थे। उन्होंने 1992 के आदेशों के तहत बढ़े हुए लाइसेंस शुल्क

को चुनौती देते हुए अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय में 1992 की रिट याचिका संख्या 238 दायर की है। चूंकि इन सभी कार्यवाहियों में कानून के सामान्य प्रश्न उत्पन्न होते हैं, इसलिए उन्हें एक साथ सुना गया है। समय-समय पर लाइसेंस शुल्क आवास और भोजन गृहों में वृद्धि को दर्शाने वाला एक चार्ट नीचे दिया गया हैः

लाईसेंस प्राप्त किये जाने वाले व्यापार एवं संचालन का विवरण	1981 से पहले प्रचलित वार्षिक लाईसेंस शुल्क	1981 में वार्षिक लाईसेंस शुल्क में वृद्धि हुई	1987 में वार्षिक लाईसेंस शुल्क में वृद्धि हुई	वार्षिक आक्षेपित आदेश में लाईसेंस शुल्क सेशोधित 1991 1992
	रूपये	रूपये	रूपये	रूपये
आवास/होटल				
जहां मासिक किराया 50/-रूपये तक है	50/-	100/-	300/-	1200/- 600/-
किराया 50/- से उपर लेकिन 100/- से ज्यादा नहीं	125/-	150/-	450/-	1800/- 900/-

किराया 100/- से ऊपर लेकिन 200/- से ज्यादा नहीं	200/-	250/-	750/-	3000/- 1500/-
किराया 200/- से ऊपर लेकिन 400/- से ज्यादा नहीं	300/-	400/-	1200/-	4800/- 2400/-
किराया 400/- से ऊपर लेकिन 600/- से ज्यादा नहीं	400/-	600/-	1800/-	7200/- 3600/-
किराया 600/- से ऊपर लेकिन 800/- से ज्यादा नहीं	500/-	800/-	2400/-	9600/- 4800/-
किराया 800/- से ऊपर लेकिन 1000/- से ज्यादा नहीं	600/-	1000/-	3000/-	12000/- 6000/-
किराया 1000/- से ऊपर लेकिन 1500/- से ज्यादा	1000/-	1500/-	4000/-	16000/- 8000/-

नहीं				
किराया 1500/- से ऊपर लेकिन 2000/- से ज्यादा नहीं	1000/-	2000/-	6000/-	24000/- 12000/-
किराया 2000/- से ऊपर लेकिन 3000/- से ज्यादा नहीं	1000/-	3000/-	9000/-	36000/- 18000/-
किराया 3000/- से ऊपर लेकिन 4000/- से ज्यादा नहीं	1000/-	4000/-	12000/-	48000/- 24000/-
किराया 4000/- से ऊपर	1000/-	5000/-	15000/-	60000/- 30000/-

याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि 1981 की बढ़ी हुई लाइसेंस शुल्क और 1992 के बाद शुल्क की प्रकृति में नहीं हैं क्योंकि कोई क्विड प्रो नहीं है। उत्तरदाताओं द्वारा लिए गए शुल्क और प्रदान की गई सेवाओं के बीच का अंतर उनके द्वारा विचाराधीन व्यापारियों को। ये कर हैं। याचिकाकर्ताओं ने

हैदराबाद नगर निगम के अध्याय VIII की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। राज्य अधिनियम, 1955 जो नगरपालिका कराधान से संबंधित है। धारा 197 के अधीन (जो अध्याय 3 के अधीन आने वाली पहली धारा है) - इस अधिनियम में निगम उन करों को अधिरोपित करेगा जो उस धारा में निर्दिष्ट हैं। धारा 197 की उप-धारा (2) के तहत निगम सरकार की पूर्व मंजूरी के अधीन उप-धारा (1) के तहत निर्दिष्ट करों के अलावा कोई भी कर लगा सकता है। कोरपरेशन से पहले धारा 198 के तहत पहली बार या नई दर पर कर लगाने का कोई भी प्रस्ताव पारित किया जाता है। यह आयुक्त को आंध्र प्रदेश राजपत्र में और स्थानीय समाचार पत्र में ऐसा करने के अपने इरादे की सूचना प्रकाशित करने का निर्देश देगा और आपत्तियों को प्रस्तुत करने के लिए एक महीने से कम की उचित अवधि निर्धारित करेगा। निगम, आपत्तियों पर विचार करने के बाद, कर लगाने के लिए संकल्प द्वारा निर्धारित कर सकता है। निगम को एक सूचना भी प्रकाशित करनी होती है जिसमें उस तारीख और उस दर को निर्दिष्ट किया जाता है जिस पर ऐसा कर या बढ़ा हुआ कर लगाया जाना है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि प्रक्रिया है लाइसेंस शुल्क को बढ़ाते समय इसका पालन नहीं किया गया जो कर की प्रकृति का है और शुल्क नहीं है और इसलिए लेवी मान्य नहीं है।

धारा 521 में उल्लिखित भोजन गृह या होटल। इन शर्तों को लाइसेंस में पुनः प्रस्तुत किया गया है। ये अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित

करते हैं कि (1) इमारत किसी उपयुक्त स्थान पर स्थित होगी और विशाल होगा और पर्याप्त होगा व्यवसाय की आवश्यकताओं के अनुसार आवास, (2) इसका निर्माण चिनाई और ऐसी अन्य गैर-ज्वलनशील सामग्री से किया जाएगा जो आयुक्त द्वारा अनुमोदित हो, (3) होटल का एक साइन बोर्ड अंग्रेजी में और कम से कम एक क्षेत्रीय भाषा में भवन के सामने लटका दिया जाएगा, (4) लाइसेंसधारी भोजन कक्ष के एक विशिष्ट भाग में एक नोटिस-बोर्ड लगाएगा जिसमें बताया जाएगा कि क्या भोजन की वस्तुएं गोमांस, मटन से बनी हैं। घी या तेल। कई अन्य शर्तें भी हैं। उदाहरण के लिए, लाइसेंसधारी होटल में आने वाले व्यक्तियों की साइकिल, मोटर कार या अन्य वाहनों की पार्किंग के लिए पर्याप्त प्रावधान करेगा। अनुज्ञप्तिधारी ऐसे परिसर में जल निकासी, वेंटिलेशन और प्रकाश व्यवस्था के लिए उपयुक्त साधन उपलब्ध कराएगा। लाइसेंसधारी रसोईघर में धुएँ के लिए

उपयुक्त आउटलेट प्रदान करेगा। अनुज्ञप्तिधारी [1999] 1 एस.सी.आर. प्रदान करेगा। दरवाजे और खिड़कियों में शटर के साथ तार गेज लगाया जाता है ताकि वे धूल और मक्खियों से सुरक्षित रहें। लाइसेंसधारी स्वस्थ पानी की अच्छी आपूर्ति प्रदान करेगा। सभी कप, तश्तरी आदि को साफ पानी से धोया जाना चाहिए। ऐसे किसी भी बर्तन का उपयोग नहीं किया जाएगा जो खराब होने की संभावना हो या जो अन्यथा भोजन की वस्तु को अप्रिय बना दे। यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बड़ी संख्या में स्थितियां हैं कि परिसर सुरक्षित और उपयुक्त हैं, भोजन स्वस्थ और स्वच्छ है और वहाँ है पर्याप्त वेंटिलेशन, जल निकासी आदि। प्रत्यर्थी-निगम को यह सुनिश्चित करने के लिए कि शर्तों का पालन किया जा रहा है। विचाराधीन परिसर का निरीक्षण करने की आवश्यकता है। खाद्य पदार्थों की बिक्री का निरीक्षण और पर्यवेक्षण करने की जिम्मेदारी भी इसकी है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि खाद्य पदार्थों की बिक्री की सभी शर्तें इस तरह के खाद्य पदार्थों की तैयारी और बिक्री से संबंधित लाइसेंस का अनुपालन किया जाता है। प्रतिवादी को इन परिसरों में स्वच्छता, कचरा हटाने और स्वच्छता बनाए रखने की भी आवश्यकता होती है। निस्संदेह, निगम का सामान्य कर्तव्य है कि वह शहर में रहने वाले सभी व्यक्तियों के लाभ के लिए शहर में कचरा हटाने और स्वच्छ स्थितियों को बनाए रखने सहित सफाई और सफाई सेवाएं प्रदान करे। फिर भी, होटल और खाने के घर अपने व्यवसाय की प्रकृति के कारण, नगर निगम पर भुगतान करने में अतिरिक्त बोझ डालते

हैं। कचरा उठाने, स्वच्छता और स्वच्छता के रखरखाव के इसके कर्तव्य क्योंकि बड़ी संख्या में लोग परिसर का उपयोग या तो रहने या खाने के लिए करते हैं। भोजन अलग-अलग घरों के विपरीत बड़ी मात्रा में तैयार किया जाता है और इसके परिणामस्वरूप कचरा भी उससे कहीं अधिक होता है जो अन्यथा घरों में होता। अलग-अलग परिवारों का मामला। वास्तव में, उक्त अधिनियम की धारा 230 के तहत प्रतिवादी-निगम के पास सहमति की विशेष दरें तय करने की शक्ति है होटल, क्लब या अन्य बड़े परिसरों के संबंध में वैन्सी टैक्स। हालाँकि, यह लाइसेंस शुल्क को कर में नहीं बदलता है।

अब तक यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि लाइसेंस शुल्क या तो नियामक या प्रतिपूरक हो सकता है। जब विशिष्ट सेवाएँ प्रदान करने के लिए शुल्क लिया जाता है प्रदान की गई सेवा और शुल्क के बीच क्विड प्रो क्वो का कुछ तत्व होना चाहिए ताकि लाइसेंस शुल्क सेवा प्रदान करने की लागत के अनुरूप हो, हालांकि सटीक अंकगणितीय समानता की उम्मीद नहीं है। हालाँकि, यह एकमात्र प्रकार का शुल्क नहीं है जो लिया जा सकता है। लाइसेंस शुल्क तब भी विनियामक हो सकता है जब उन गतिविधियों को विनियमित या नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है जिनके लिए लाइसेंस दिया जाता है। ऐसी गतिविधि के लिए विनियमन के लिए जो शुल्क लिया जाता है, वह वैध रूप से शुल्क के रूप में वर्गीकृत किया जा

सकता है न कि कर हालांकि कोई सेवा प्रदान नहीं की जाती है। इस तरह के शुल्क के उद्ग्रहण के लिए क्विड प्रो क्वो के तत्व की आवश्यकता नहीं है, हालांकि इस तरह के शुल्क अत्यधिक नहीं हो सकते हैं।

आयुक्त के मामले में, हिंदू धार्मिक दान, मद्रास बनाम. श्री शिरपुर मठ के श्री लक्ष्मींद्र तीर्थ स्वामी, [1954] एस. सी. आर. 1005 इस सवाल से निपटने वाले शुरुआती मामलों में से एक है कि क्या लेवी शुल्क है या कर, इस अदालत ने माना कि संविधान और विशेष रूप से संविधान की अनुसूची VII में विधायी प्रविष्टियां एक स्पष्ट अंतर बताती हैं। कर और शुल्क के बीच का संबंध। उच्च न्यायालय ने ऑस्ट्रेलिया के उच्च न्यायालय के लैथम सी. जे. द्वारा दी गई "कर" की परिभाषा को पुनः प्रस्तुत किया। मैथ्यूज बनाम। चिकोरी मार्केटिंग बोर्ड, (60 सी.एल.आर. 263,276)। "विद्वान मुख्य न्यायाधीश के अनुसार" एक कर अनिवार्य है। कानून द्वारा प्रवर्तनीय सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा धन का निष्कासन और प्रदान की गई सेवाओं के लिए भुगतान नहीं है। दूसरी ओर एक शुल्क को आम तौर पर एक विशेष सेवा के लिए एक शुल्क के रूप में परिभाषित किया जाता है। कुछ सरकारी एजेंसियों द्वारा विभाजन। प्रभारित शुल्क की राशि सरकार द्वारा किए गए खर्चों पर आधारित मानी जाती है। सेवा प्रदान करना हालांकि कई मामलों में लागत मनमाने ढंग से निर्धारित की जाती है। आम तौर पर, शुल्क समान होते हैं और इसका कोई हिसाब

नहीं लिया जाता है। भुगतान करने के लिए विभिन्न प्राप्तकर्ताओं की अलग-अलग क्षमताएँ। ये निस्संदेह विभिन्न प्रकार के शुल्कों की कुछ सामान्य विशेषताएँ हैं। ऐसी परिभाषा तैयार करना संभव नहीं है जो सभी मामलों पर लागू हो। न्यायालय ने तब कहा (पृष्ठ 1042 पर), "कर और शुल्क के बीच का अंतर मुख्य रूप से इस तथ्य में निहित है कि कर इस अधिनियम के एक भाग के रूप में लगाया जाता है। सामान्य बोझ, जबकि शुल्क एक विशेष लाभ या विशेषाधिकार के लिए भुगतान है। शुल्क एक विशेष क्षमता प्रदान करते हैं, हालांकि विशेष लाभ, उदाहरण के लिए, दस्तावेजों या विवाह लाइसेंस के लिए पंजीकरण शुल्क के मामले में, सार्वजनिक हित में विनियमन के प्राथमिक उद्देश्य के लिए गौण है। कर और शुल्क के बीच वास्तव में कोई सामान्य अंतर नहीं है और जैसा कि सेलिगमैन ने कहा है, किसी राज्य की कर लगाने की शक्ति तीन अलग-अलग रूपों में प्रकट हो सकती है।

कलकत्ता निगम और अन्य बनाम लिबर्टी सिनेमा, [1965] 2 एस.सी.आर. के मामले में, यह न्यायालय संविधान का उल्लेख करने के बाद शुल्क और कर के बीच अंतर करने वाले राष्ट्रीय प्रावधानों में यह भी कहा गया है कि हमारे संविधान में लाइसेंस के लिए शुल्क और प्रदान की गई सेवाओं के लिए शुल्क को विभिन्न प्रकार के शुल्क के रूप में माना गया है। पूर्व का उद्देश्य प्रदान की गई सेवाओं के लिए शुल्क होना नहीं है

यह अनुच्छेद 110 (2) और अनुच्छेद 199 (2) के विचार से स्पष्ट है जहां दोनों का उल्लेख किया गया है। सायन का उपयोग यह दर्शाने के लिए किया जाता है कि वे समान नहीं हैं। दूसरे शब्दों में, सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट प्रदान की गई सेवाओं के लिए शुल्क और नियामक शुल्क के बीच अंतर किया गया था। भारतीय अभ्रक और मिकानाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम बिहार राज्य आेर अन्य [1971] सप. पृष्ठ 324 पर एस.सी.आर. 319; ओम प्रकाश अग्रवाल आदि। गिरि राज किशोरी और अन्य, [1986] 1 एस.सी.आर. 149 और नगर परिषद, मदुरै बनाम आर. नारायणन आदि, [1976] 1 एस.सी.आर. 333 पृष्ठ 339 से 400 पर न्यायालय ने एक शुल्क पर विचार किया था जो प्रदान की गई सेवाओं के लिए लिया गया था। में इस तरह के प्रतिपादन की लागत के बीच एक सामान्य चरित्र का सह-संबंध सेवा और प्रभारित शुल्क। कई अन्य निर्णयों का भी उल्लेख किया गया। कृषि उपज मंडी समिति और अन्य के मामले में संक्षेप में। वी. ओरिएंट पेपर और इंडस्ट्रीज लिमिटेड, [1995] पैराग्राफ 21 में 1 एस.सी.सी. 655

वर्तमान मामले में, हालांकि, प्रभारित शुल्क केवल इसके लिए नहीं हैं प्रदान की जाने वाली सेवाएं लेकिन उनमें नियामक शुल्क का एक बड़ा तत्व भी होता है यह सुनिश्चित करने के लिए लाइसेंसधारियों की गतिविधि की निगरानी के उद्देश्य से लगाया गया कि वे लाइसेंस के नियमों और शर्तों

का पालन करते हैं। इनसे निपटना वैम ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड और ए.एन.आर. में इस न्यायालय ने ऐसे विनियामक शुल्कों को लागू किया है। आदि। वी.यू.पी. और अन्य का राज्य। आदि., [1997] 2 एस.सी.सी. 715 ने पृष्ठ 726 पर कहा कि एक नियामक शुल्क के मामले में कोई क्विड प्रो क्वो आवश्यक नहीं था लेकिन इस तरह के शुल्क अति नहीं होनी चाहिए। विनियामक और के बीच एक ही अंतर पी. कन्नदासन और अन्य के मामले में क्षतिपूर्ति शुल्क लगाया गया है। वी.टी.एन. और अन्य का राज्य। [1996] 5 पैराग्राफ 36 में एस.सी.सी. 670 के साथ-साथ त्रिपुरा और अन्य बनाम सुधीर रंजन नाथ, [1997] 3 एस.सी.सी. 665, 673 पर।

हालाँकि, याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया कि शुल्क वास्तव में लिया गया था, इस मामले में मौजूद क्विड प्रो क्वो का तत्व, तरीके से एकत्र की गई राशि शुल्क की राशि नगर निगम की सामान्य निधि में जमा की जाती थी। हैदराबाद नगर निगम अधिनियम, 1955 की धारा 169 के तहत नगरपालिका निधि का गठन किया जाता है और उक्त धारा के तहत यह इस प्रकार प्रदान किया जाता है -

निम्नलिखित हैः

"169 नगरपालिका कोष का गठन (1) प्रावधानों के अधीन इस अधिनियम और नियमों और उप-कानूनों के

(ए) निगम द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी धन इस अधिनियम या कुछ समय के लिए किसी अन्य कानून के प्रावधान बल, या किसी अनुबंध के तहत।

(बी).....

(सी).....

(डी) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लगाए गए किसी भी कर द्वारा जुटाए गए सभी धन

(ई) इस अधिनियम के तहत या इसके तहत लागू किसी किसी नियम, उप-कानून या स्थायी आदेश के तहत देय और लगाए गए सभी शुल्क और जुर्माना,

(एफ).....

(जी).....और

(एच) निगम से संबंधित किसी भी धन के संबंध में किसी भी निवेश या किसी लेनदेन से उत्पन्न होने वाले सभी ब्याज और लाभ को एक ऐसी निधि में जमा किया जाएगा जिसे नगरपालिका निधि 'और जो निगम द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए न्यास में रखी जाएगी, इसमें दिए गए प्रावधानों के अधीन रहते हुए निहित है

(2).....

धारा 174 उस उद्देश्य का वर्णन करती है जिसके लिए नगरपालिका निधि का उपयोग किया जाना है। इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि चूंकि सभी शुल्क सामान्य नगरपालिका निधि का एक हिस्सा हैं, और इस निधि को विभिन्न कार्यों के लिए लगाया जाना है। नगर निगम के उद्देश्यों के लिए, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके द्वारा एकत्रित शुल्क का उपयोग नियामक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। हालाँकि, इस न्यायालय में सिरसिल्क लिमिटेड और अन्र का मामला। वी. वस्त्र समिति और अन्य। [1988] सप. 2 एस.सी.आर. 880 ने पृष्ठ 910,912 पर बताया है कि नियामक शुल्क के मामले में एक अलग निधि आवश्यक नहीं है।

वर्तमान मामले में उत्तरदाताओं द्वारा बजट अनुमान नियमों पर भरोसा किया जाता है ताकि यह दिखाया जा सके कि शुल्क का उपयोग इसके लिए किया जा रहा है। विनियामक सेवाएँ। हैदराबाद नगर निगम के बजट नियम, 1968 में नियम 6 के तहत निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:

"6. बजट को मंजूरीः परिषद, निम्नलिखित बिंदुओं पर खुद को संतुष्ट करने के बाद प्रत्येक वर्ष इस तरह के संशोधन के साथ आम तौर पर 20 फरवरी के बाद बजट को मंजूरी देगी। जो आवश्यक लगेः

(ए).....

बशर्ते कि किसी भी शुल्क या शुल्क के तहत प्राप्तियों का कोई हिस्सा न हो सेवाओं के प्रदर्शन के लिए एकत्र या पुनर्प्राप्त जैसे कि वध गृह शुल्क, बाजार शुल्क और किराया, भवन परमिट शुल्क, लेआउट शुल्क, लाइसेंस शुल्क और इसी तरह का उपयोग या खर्च किया जाएगा। किराए के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए संग्रहित। कोई भी शेष अधिशेष या अप्रयुक्त राशि होगी -एक आरक्षित निधि में निवेश किया।

शुल्क, हालांकि सामान्य निधि में जमा किया जाता है, इसके लिए निर्धारित किया जाता है। जिन उद्देश्यों के लिए उन्हें एकत्र किया जाता है। इसलिए, इरादा एक शुल्क लगाने का है जिसका उपयोग नियामक और क्षतिपूर्ति के लिए किया जाएगा। वर्तमान मामले में उद्देश्य। याचिकाकर्ताओं का यह तर्क कि यह शुल्क की आड़ में एक कर है, टिकाऊ प्रतीत नहीं होता है।

हालाँकि, याचिकाकर्ताओं द्वारा यह तर्क दिया गया है कि यदि यह एक शुल्क है, तो लगाए गए शुल्क की मात्रा अत्यधिक है। यह भी अनुचित है क्योंकि जिस तरीके से शुल्क लगाया जाता है, उसका उस उद्देश्य से कोई संबंध नहीं है जिसके लिए शुल्क लगाया जाता है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि लाइसेंस शुल्क के आधार पर उस परिसर के संबंध में देय किराया जिसमें भोजन गृह या आवास की गतिविधियाँ की जाती हैं, शुल्क लेने के लिए उचित आधार नहीं है। एक शुल्क क्योंकि परिसर के लिए लिए गए

किराए का उससे कोई संबंध नहीं है निगम द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं।

सबसे पहले यह आवश्यक नहीं है कि शुल्क केवल में होना चाहिए एकमुश्त शुल्क का रूप। वर्तमान मामले की तरह शुल्क को भी वर्गीकृत किया जा सकता है। निगम ने शुल्क की मात्रा के लिए मानदंड के रूप में भुगतान किए गए किराए की मात्रा को चुना है। उस संबंध में कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत किराए का कब्जे वाले क्षेत्र के साथ संबंध है। रहने का घर या खाने का घर। द्वारा की गई गतिविधियों के मामले में इनमें से कोई भी आवास और भोजन गृह, उनके कब्जे वाला क्षेत्र व्यावसायिक गतिविधियों के विस्तार के साथ इसका सीधा संबंध है। इसकी आवश्यकता स्वच्छता और स्वच्छता, कचरे का उत्पादन और इसकी सीमा विनियमन जिसकी आवश्यकता हो सकती है, परिसर के आकार पर निर्भर करता है। जो बदले में गतिविधि की सीमा को नियंत्रित करता है। निसन्देह किसी दिए गए मामले में यदि परिसर पुराने हैं, किराया कम हो सकता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भुगतान किए गए किराए के आधार पर परिसर को वर्गीकृत करने का इससे कोई संबंध नहीं है। प्रभारित शुल्क की मात्रा।

एक यह भी तर्क दिया जाता है कि प्रभारित शुल्क अत्यधिक हैं। जवाब रिट याचिका में दायर अपने जवाबी हलफनामे में सामान्य आंकड़े

दिए गए हैं जो यह दर्शाते हैं कि आधार पर व्यापार लाइसेंस शुल्क से कुल आय 1987 की दरें रूपये 1,08,25,588 संशोधित अनुमानों के अनुसार। 1992 में लाइसेंस शुल्क में वृद्धि के साथ आय दोगुनी होकर रूपये 2,16,51,176 यह स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त नहीं होगा। कचरा उठाने, सड़कों की सफाई, स्वच्छता, चिकित्सा सहित सेवाएं केंद्र, नियोजित कर्मचारियों का वेतन आदि। सार्वजनिक स्वास्थ्य बजट निगम की प्रासंगिक अवधि के लिए लगभग रूपये 13,95,40,000 बेशक, ये आंकड़े अलग से विस्तार का संकेत नहीं देते हैं। उनकी सेवाएँ। वर्ष 1981-82 के संबंध में जब पहली वृद्धि जो चुनौती के तहत है, लाइसेंस से आय के आधार पर 1981 में बढ़ाई गई दरें रूपये 37,89,627 जबकि निगम के लाइसेंस अनुभाग और स्वच्छता अनुभाग पर खर्च रूपये 3,85,11,961 निगम ने यह भी बताया कि वार्षिक वेतन वर्ष 1981 में नगर निगम के विभिन्न खंडों में लाइसेंस से संबंधित कर्मचारियों के लिए बिल रूपये 40,45,585 उसी का वेतन 1992 में कर्मचारी रूपये 1,75,31,943 निगम का प्रयास यह दिखाना है कि 1981 और 1992 के बीच विभिन्न मदों के तहत खर्च दोगुने से अधिक हो गया था। इसलिए, लाइसेंस शुल्क में वृद्धि जो 1972 के बाद पहली बार 1981 में की गई थी और 1992 में लाइसेंस शुल्क में वृद्धि भी सेवाओं को प्रदान करने की लागत में वृद्धि के साथ सह-संबंधित थी-चाहे वह नियामक हो या अन्यथा विचाराधीन व्यापारों के लिए। उत्तरदाताओं ने अपने हलफनामे में वर्ष 1989-90 के लिए बजट

अनुमान भी संलग्न किए हैं ताकि यह दिखाया जा सके कि एकत्र किए गए लाइसेंस शुल्क बहुत कम हैं। स्वास्थ्य सेवाओं, स्वच्छता, लाइसेंस अनुभाग आदि से निपटने के लिए नगर निगम की आवश्यकताओं की तुलना में। बजट अनुमानों में 1988-89 उदाहरण के लिए होटलों से लाइसेंस शुल्क अनुमानित रूपये 25,00,000 बजट के अनुसार वर्ष के लिए राजस्व व्यय 1988-89 स्वच्छता, संरक्षण और सफाई अनुभाग के तहत टैब्लिशमेंट खर्च, वेतन और भत्तों सहित समय सीमा रूपये 10,14,61,100, जबकि स्वास्थ्य कार्यालय अनुभाग के तहत ये हैं रूपये 31,30,400, खाद्य मिलावट और नगरपालिका की रोकथाम के तहत प्रयोगशाला खंड में, अनुमानित व्यय रूपये 7,66,200, निस्संदेह, यह खर्च न केवल विचाराधीन व्यापारों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं को शामिल करता है। इसमें विभिन्न अन्य व्यवसायों को प्रदान की जाने वाली सेवाएं भी शामिल हैं, व्यक्तियों और संगठनों और जनता के अन्य सभी सदस्यों के लिए जो नगर निगम द्वारा प्रदान की जाने वाली ऐसी सेवाओं से लाभ। कभी नहीं। कम से कम, इस तथ्य को देखते हुए कि एकत्र किए गए लाइसेंस शुल्क केवल एक बहुत नगर निगम द्वारा किए गए कुल व्यय का एक छोटा सा हिस्सा, हम इन शुल्कों के शुल्क को अत्यधिक मानने के इच्छुक नहीं हैं। यह भी है यह ध्यान रखना आवश्यक है कि 1981 में आक्षेपित वृद्धि पहली वृद्धि थी 1972 के बाद। उच्च न्यायालय ने सही माना है कि हैदराबाद द्वारा की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों की लागत में वृद्धि को देखते हुए नगर निगम, नौ

साल के बाद लाइसेंस शुल्क को दोगुना नहीं कर सकता इसे अत्यधिक वृद्धि माना जाता है। लाइसेंस शुल्क के 1987 के स्तर से 1992 के स्तर तक की वृद्धि के संबंध में, प्रारंभिक वृद्धि इसे अत्यधिक माना जा सकता था। लेकिन अभ्यावेदन के बाद थे प्रत्यर्थी को किया गया-लाइसेंस शुल्क में वृद्धि से प्रभावित विभिन्न व्यापारियों द्वारा निगम ने वृद्धि को कम कर दिया और इसे 1987 में लिए गए लाइसेंस शुल्क से दोगुना रखा। इस संबंध में उत्तरदाताओं ने विभिन्न पक्षों के साथ बैठकें और विस्तृत बातचीत की। भोजनालयों के संचालन से जुड़े व्यापार संगठन और आवास। उत्तरदाताओं ने कार्यवाही के कार्यवृत्त को संलग्न किया है। आयुक्त के सामने। हैदराबाद नगर निगम, दिनांकित 25.7.1992, 25.7.1992 की बैठक में लाइसेंस बढ़ाने पर चर्चा की गई कुछ व्यापारों और संचालन का शुल्क। इनमें वर्तमान व्यापार शामिल हैं और व्यवसाय। कार्यवाही में दर्ज किया गया है कि व्यापारियों ने वृद्धि देखी उच्च पक्ष के रूप में मौजूदा दरों से और कई मामलों में वृद्धि मौजूदा दरों का चार से पांच गुना थी। वृद्धि से व्यथित लाइसेंस शुल्क, व्यापारियों ने एक जुड़वां शहरों के व्यापारियों की संयुक्त कार्रवाई समिति का गठन किया टी और विभिन्न स्तरों पर प्रतिनिधित्व किया। संयुक्त बैठकें आयोजित की गईं 224 अप्रैल, 6 मई, 11 मई और 12 मई, 1992 और एक बड़े सौदे के बाद विचारों का आदान-प्रदान, व्यापार लाइसेंस बढ़ाने का सर्वसम्मति से संकल्प लिया गया अक्टूबर, 1991 में वृद्धि से पहले प्रचलित दरों पर 100% द्वारा शुल्क। इसके लिए समझौता हो

गया है। इन प्रस्तावों को स्वीकार किया गया निगम की स्थायी समिति और सामान्य निकाय। समझौता क्रमशः, संशोधित दरों को लागू किया गया। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सदस्य इस वृद्धि पर सहमत नहीं थे। फिर भी, व्यापारियों का संयुक्त कार्रवाई समिति जिसमें कई अन्य व्यापारी शामिल थे व्यापार इस वृद्धि को उचित मानने के लिए सहमत हुआ। इसलिए, यह नहीं होगा, इस सहमत वृद्धि को अत्यधिक कहना या यह संकेत देना उचित होगा कि यह यह शुल्क के बजाय कर लगाने का उपाय था।

याचिकाकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया था कि यदि यह बढ़ा हुआ शुल्क है हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि जो लाइसेंस शुल्क लिया जाता है वह एक नियामक-सह-क्षतिपूर्ति शुल्क है, और यह कर नहीं है, हम इसकी जांच नहीं कर रहे हैं। यह सवाल इसलिए है क्योंकि इस शुल्क को कर के रूप में देखना आवश्यक नहीं है।

इसलिए हम उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए निष्कर्षों से सहमत हैं। इसलिए, अपीलों के साथ-साथ रिट याचिका भी खारिज कर दी जाती है। वहाँ हालाँकि, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

वी.एस.एस.

याचिका और अपील खारिज कर दी गई।

(यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी **श्रीमती भाविका कुलहरी** (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।)